Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

2019 के आम चुनाव में महिलाओं की स्थितिः एक अवलोकन

डाँ उश्मान गणी

प्रारूप -समाज मे महिलओं की स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय रही हैं और उन्हें अपने हक के लये संघर्ष करना पड़ा है. समाज का समग्र वकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है।वर्तमान आलेख मे महिलओं की स्थिति एवम् उनके भारतीय राजनीति में भा गदारी का वश्लेषण कया गया हैं। राजनीति में महिलाओं की भू मका बहुत व्यापक है , जो न सर्फ मता धकारऔर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने भर पर निर्भर करता है , बिल्क निर्णय लेने की प्रक्रया, राजनीतिक संक्रयता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से संबंधत है। बीज शब्द- राजनीति, राजनीतिक संक्रयता, राजनीतिक चेतना, मता धकार, लैं गक असमानता।

राजनीति में महिलाओं की भू मका बहुत व्यापक है, जो न सर्फ मता धकारऔर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने भर पर निर्भर करता है , बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रया , राजनीतिक स क्रयता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से संबं धत है। हालां क भारत में महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं , आज की स्थिति में नारी की सहज भू मका अनिवार्य रूप से प्रत्येक हिष्ट से आवश्यक है। महिलाओं की स्थिति से कसी भी समाज की श्रेष्ठता तथा हीनता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था में पारिस्थितकी , वकास और लंगभेद के मुद्दे चुनौतिपूर्ण है, समानता के आदर्श की बातें करने वाले लोग , राजनीतिक दल, लोकसभा, वधानसभा, ग्रामपंचायतों में महिलाओं को लेते ही नहीं, जो एक अत्यंत वचारणीय बिंदु है। स्वतंत्रता भारत के संवधान की एक महत्वपूर्ण वषेषता यह है क इसमें प्रत्येक महिला पुरूष को समान अ धकार प्रदान कये गये। महिलाओं की स्थिति पुरूषों के समकक्ष बनाने तथा उनको वकास के अवसर उपलब्ध करवाने के लये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। संवधान में महिलाओं के लये समानता एवम् उनके अ धकारों के लये अनुच्छेद 14 , 15, 16, 23, 39, 39क, 42 में वशेष प्रावधान कये गये हैं।

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

गाँधी जी के अन्सार "स्त्रियों को मता धकार तो होना ही चाहिये, कानून के तहत समान दर्जा भी मलना चाहिये।" सं वधान की धारा 15 के तहत - "स्त्री प्रूष के बीच कसी भी मामले में भेदभाव नहीं कया जायेगा। "इन सभी उपर ल खत तथ्यों को देखते ह्ये यह कहा जा सकता हैं क नारी की स्थिति संवैधानिक रूप से अत्यंत ही दयनीय तो नहीं हैं , ले कन चंताजनक अवश्य है। सं वधान के द्वारा महिलाओं को यद्य प व भन्न संवैधानिक अ धकार प्रदान कये गये हैं तथा प वास्त वक स्थिति कुछ और ही परिदृष्य दृष्टिगोचर होता है। महिलाओं को सेवा प्रदान करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संस्थाये तथा योजनायें या तो काम नहीं करती और यदि करती भी हैं तो उनकी कोई स्चारू रूपरेखा नहीं होती , जिससे महिला अ धकारों का हनन होता है। महिलाओं को उनके अधकारों से भी वंचत कया जाता है , जैसे कानूनी सहायता लेने का अ धकार। लोकतंत्र एवम् महिला अ धकारिता राजनीतिक प्रक्रया के वकास में एक अनिवार्य कदम है। इसका उद्देष्य महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाना और उन्हें कसी भी प्रकार के प्रतिबंध और अलगाव से मुक्ति दिलाना है। महिलाओं की राजनीतिक अधकार प्रदान कये जाने की परिकल्पना, उनके उत्थान के लये और लैं गक असमानता एवम् भेदभाव उन्मूलन हेत् एक सषक्त एवम् अनिवार्य माध्यम के रूप में की गयी है। इसी के अनुरूप भारतीय महिलाओं को कुछ संवैधानिक अधकार प्रदान करता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुरुषों और महिलाओं को उनके लंग भेद के बावजूद समान शक्तियां और भू मका देती है, जिसका प्रमाण देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल और वदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, लोकसभा अध्यक्ष सु मत्रा महाजन, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी, I&B मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वर्तमान राजस्थान की मुख्यमंत्री सुश्री वसुंधरा राजे संधया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती के रूप मे देखा जा सकता हैं। आधुनिक भारतीय राजनीति में प्रमुख और निर्णायक भू मका निभायी रही है।

महिलाओं के लए राजनीतिक सुधार आ र्थक आत्मिनर्भरता , बेहतर स्वस्थ देखभाल और सुधार शक्षा शा मल होना चाहिए। हमें एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था वक सत

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

करने की जरूरत है जो क वोट बैंक, पैसा और बाहुबल के गंदे खेल नहीं बल्कि एक बड़े संयुक्त परिवार के रूप में राष्ट्र के समग्र वकास के लए एक सकारात्मकता लाएं। इस लए वास्तव में निष्पक्ष राजनीतिक संस्कृति सुनिश्चित करने के लए, यह महत्वपूर्ण है क राजनीति को दशकों से पल रही कुरीतियों से मुक्त कया जाए।

108 वें (2009)सं वधान संशोधन में 50 % कर दिया गया है। जब क राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन प्रतिनि धत्य 42 % ही है। यद्य प सरकार की ओर से महिलाओं को कानूनी संरक्षण और अधकार देने का जो दिखावा हो रहा है , वो तो मात्र महिलाओं को भ्र मत करने का मात्र एक जिरया है। सच्चाई तो यह है क आज भी महिलाओं को वे अधकार प्राप्त नहीं हुये हैं, जिनकी वे सही मायने में अधकारी हैं और यदि सघंषे के बाद अधकार मल भी जाते हैं तो उनके प्रयोग हेतु वे स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें पहले की तरह अपनी वर्चस्विता दिखाने का मौका आज भी नहीं मल पाया है। आज महिलायें आ र्थक , राजनीतिक और सामाजिक दासता से निकलकर स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयास कर रही है ,ले कन स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। अतः यह आवश्यक है क देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हो। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का आशय नीति निमार्ण में भागीदारी से है। यह भागीदारी मतदाता से लेकर पंचायती राज , लोक सभा, राज्य सभा, संसद से हो सकती है। परन्तु वास्त वक रूप से महिलायें राजनीतिक क्षेत्र में अब तक वह मुकाम प्राप्त नहीं कर पायीं हैं, जितने आशा की गई थी। इस क्षेत्र में उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ है जैसे व भन्न सामाजिक कुरीतियाँ , अषक्षा, वत्तीय समस्या , राजनीतिक अज्ञानता , पुरूष प्रधान समाज , मान सकता, पर्दा प्रथा आदि अन गन बाधायें है जिन्हें दूर करना परम आवष्यक हैं।

हमारी व्यवस्था में सर्वोच्च वधायी संस्थान हमारी संसद है जो पूरे देश की नीति का निर्धारण करती है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है क जब तक संसद में महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कया जाता, अपने सशक्तीकरण के लए औरतें सदैव पुरुषों की परमुखापेक्षी बनी रहने के लए अभशप्त होंगी। इस लहाज से देखें तो लोक सभा में महिला सांसदों की सहभा गता में स्वतन्त्रता के बाद के समय से अब तक बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आए हैं। सं वधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी जिसमें महिला सदस्यों की

Vol.9 Issue 11, November 2019, ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संख्या मात्र 15 थी। यह हिस्सेदारी मात्र 5% के करीब बैठती है। उस समय से लेकर अब तक महिलाओं की भागीदारी कभी भी 20% तक नहीं हो पाई है जो निम्न ल खत ता लका से स्पष्ट है:

लोक	कालाव ध	कुल सदस्य	महिला सांसदों	महिलाओं की
सभा		संख्या	की संख्या	हिस्सेदारी(%)
क्रमांक				
पहली	1952-1957	489	22	04.50
दूसरी	1957-1962	494	27	05.47
तीसरी	1962-1967	494	34	06.88
चौथी	1967-1971	520	31	05.96
पाँचवीं	1971-1977	543	22	04.05
ন্ত ী	1977-1980	543	19	03.50
सातवीं	1 980-1 985	543	28	05.16
आठवीं	1 984-1 985	543	44	08.10
नौवीं	1 989-1 991	543	28	05.16
दसवीं	1991-1996	543	36	06.63
ग्यारहवीं	1996-1998	543	40	07.37
बारहवीं	1 998-1 999	543	44	08.10
तेरहवीं	1999-2004	543	48	08.84
चौदहवीं	2004-2009	543	45	08.29
पंद्रहवीं	2009-2014	543	59	10.87
सोलहवीं	201 4-201 9	543	62	11.42
सत्रहवीं	2019-	543	78	14.36

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

आज राजनीतिक स्तर पर यद्य प महिलाओं की संख्या कम है ले कन एक तथ्य स्पष्ट है क जितनी भी महिलायें राजनीति स्तर पर आयी हैं, उनका कार्य स्पष्ट, पारदर्शक है और वे संभवतया भ्रष्टाचार और भेदभाव रहित होकर अपने कार्यों को संपूर्ण करती है। भारत में उदारीकरण का दौर शुरू होने पर महिलाओं की स्थिति में तेजी से परिवर्तन देखने को मला। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के फैलाव ने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जिनमें महिलाओं की संख्या भी उल्लेखनीय रही। नए प्रौद्यों गकी और शक्षा के प्रसार ने महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना शुरू कया उनकी सामाजिक स्थिति के साथ -साथ आ र्थक स्थिति भी मजबूत हुई। आज सरकार और उद्योग पूरे ज़ोर से वदेशी पूंजी निवेश को आक र्षत करने में लगे हैं ले कन उदारीकरण व ढांचागत समायोजन नीतियों के प्रभाव के अध्ययन के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा क भारत एक तीसरी दुनिया का देश है और काफी समय तक उपनिवेश रहा है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग के पीछे सर्फ यही सोच नहीं है क उनकी मौजूदगी बढ़े बल्कि यह भी है क राजनीतिक वमर्श में उनकी भागीदारी हो जिसमें अवसरवादिता, लैं गक भेदभाव और अति-पुरुषवादी वमर्श हावी है। ले कन प्रयंका चतुर्वेदी का कांग्रेस से शव सेना जैसी घटनाएं एक दुखद वडंबना की ओर संकेत करती हैं। चतुर्वेदी का आरोप है क उन्होंने कांग्रेस इस लए छोड़ी क्यों क उनके खलाफ अभद्र व्यवहार करने वालों के खलाफ पार्टी ने कदम नहीं उठाए। ले कन वे वैसी पार्टी में गईं जिसने कभी उन मूल्यों का महत्व नहीं दिया जिसकी बात प्रयंका चतुर्वेदी कर रही हैं। इसके बावजूद प्रयंका चतुर्वेदी महिलाओं के अधकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही हैं।

इस तरह की घटनाएं राजनीति के 'नई' सामान्य बातों की ओर इशारा करती हैं। इसमें बगैर कसी ग्लानी के नंगा करियरवाद हावी दिखता है। ऐसे में इस सोच की परीक्षण की जरूरत है। इस घटना से यह भी पता चलता है क पार्टियों के लए उनके सदस्य उनके कर्मचारी की तरह हैं जिनका काम है पार्टी के ब्रांड और छ व की मार्केटिंग करना। ऐसे लोगों को नेता मानना भी ठीक नहीं है। क्यों क इनका न तो लोगों से संबंध होता है और न ही पार्टी की वचारधारा

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

से। ऐसे में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना सामान्य है क्यों क इसे काॅरपोरेट संस्कृति का हिस्सा मान लया गया है।

इसमें दिक्कत इस बात को लेकर भी है क महिला अधकारों की बात बहुत सी मत दायरे में होती है। एक तरफ तो अष्ट राजनीति की स्वीकार्यता है तो दूसरी तरफ इसके खलाफ संघर्ष का ढोंग भी है। असली नारीवाद तो यह है क राजनीति में एक नए तरह की भाषा उपजे। इस वजह से ही लोकतांत्रिक सदनों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठ रही है। क्या महिला नेताओं का यह रवैया महिलाओं की मदद कर रहा है जिसमें उन्हें लगता है क सफल होने के प्रूषों की तरह काम करना होगा?

राजनीतिक परिदृश्य में महिला प्रतिनि धयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लए आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। पछले लोकसभा चुनाव में सर्फ 11 प्रतिशत महिलाएं सांसद बन पाई थीं। इसका मतलब यह हुआ क 90 लाख महिलाओं पर एक महिला सांसद थी। आरक्षण की मांग और महत्वपूर्ण इस लए भी हो जाती है क्यों क पार्टियां महिलाओं को अपेक्षा के मुताबिक टिकट नहीं दे रही हैं। पार्टियां उन्हीं महिलाओं को टिकट दे रही हैं जो च र्चत रही हों या जिनकी कोई राजनीतिक वरासत हो। अ धकांश पार्टियां अपनी उन महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। अगर महिलाओं को टिकट मलता भी है तो भी उनकी राह आसान नहीं है। पूरे चुनाव प्रक्रया में व भन्न स्तर पर प्रूषों का वर्चस्व है।

महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे प्रतिनि धयों की जरूरत है जो अपनी मांगों को सही ढंग से उठा सकें और एक नई राजनीतिक संस्कृति के वकास में अपनी भू मका निभा सकें। इन प्रतिनि धयों को कार्यबल में महिलाओं की घटती भागीदारी और मतदाता सूची में दो करोड़ महिलाओं के नहीं शा मल होने के मुद्दों को उठाना चाहिए। उन्हें महिलाओं के मुद्दों को वस्तार देने की को शश करनी चाहिए।

वास्त वक प्रतिनि धत्व का मतलब यह है क अलग-अलग पृष्ठभू म वाली महिलाओं को आवाज मले और इससे राजनीति में नई संवेदना वक सत हो। यह जरूरी है क लोकतंत्र और

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नारीवाद के मूल्यों में वश्वास पैदा कया जाए न क आक्रामक पुरुषवाद और हिंसक सोच का समर्थन कया जाए। नारीवाद के प्रति सर्फ बात करने से स्थित नहीं सुधरेगी और न ही इससे रवैये में कोई बदलाव आएगा। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से रवैये में बदलाव तो आएगा ले कन डर इसी बात की है क वही राजनीतिक संस्कृति नहीं मजबूत हो जिसमें राजनीति में बने रहने के लए पुरुषों की तरह काम करने पर जोर होता है।

17वीं लोकसभा के वजयी उम्मीदवारों में महिलाओं की कुल संख्या 78 है। महिला सांसदों की अब तक की इस सर्वा धक भागीदारी के साथ ही नई लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 17 प्रतिशत हो जाएगी। महिला सांसदों की सबसे कम संख्या 9वीं लोकसभा में 28 थी। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा की 542 सीटों के लए शुक्रवार को घो षत पूर्ण परिणाम के आधार पर सर्वा धक 40 महिला उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर सर्फ पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने महिला उम्मीदवार के रूप में रायबरेली से जीत दर्ज की है।

गौरतलब है क लोकसभा चुनाव में कुल 8049 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 724 मिहला उम्मीदवार थीं। मौजूदा लोकसभा में मिहला सांसदों की संख्या 64 है। इनमें से 28 मौजूदा मिहला सांसद चुनाव मैदान में थी। चुनाव हारने वाली प्रमुख मिहला उम्मीदवारों में कन्नौज से एसपी सांसद डंपल यादव, रामप्र से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा शा मल हैं।

कांग्रेस ने सर्वा धक , 54 और बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। अन्य राष्ट्रीय पार्टियों में , बीएसपी ने 24, तृणमूल कांग्रेस ने 23, मार्क्सवादी कॉम्युनिस्ट पार्टी ने 10, भारतीय कॉम्युनिस्ट पार्टी ने चार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनि धत्त्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले चुनाव में सदन में केवल 5% महिलाएँ थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 14.3% हो गई हैं।

प्रमुख बिंदु

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर
 38 हो गई है जो क अब तक की सबसे
 39 धक संख्या है।
- हालाँ क वृहद् स्तर पर देखें तो यह संख्या अभी भी कम है क्यों क यह आनुपातिक प्रतिनि धत्त्व के आस-पास भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है क अमेरिका में यह आँकड़ा
 32% है, जब क पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21% है।
- वर्ष 1962 से अभी तक लगभग 600 मिहलाएँ सांसद के रूप में चुनी गई हैं। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से लगभग आधे (48.4%) ने वर्ष 1962 के बाद कसी मिहला को सांसद के रूप में नहीं चुना है।
- आज़ादी के बाद केवल 15वीं और 16वीं लोकसभा में मिहलाओं के प्रतिनि धत्व में बढ़ोतरी देखने को मली, जो इससे पहले 9% से कम रहती थी।
 क्या हैं प्रमुख चुनौतियाँ
- महिलाओं को नीति निर्धारण में पर्याप्त प्रतिनि धत्त्व न मलने के पीछे निरक्षरता भी एक बड़ा कारण है। अपने अ धकारों को लेकर पर्याप्त समझ न होने के कारण महिलाओं को अपने मूल और राजनीतिक अ धकारों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है।
- शक्षा, संसाधनों संपत्ति का स्वा मत्व और रोज़मर्रा के काम में पक्षपाती दृष्टिकोण जैसे मामलों
 में होने वाली लैं गक असमानताएँ महिला नेतृत्व के उभरने में बाधक बनती हैं।
- कार्यों और पिरवार का दायित्वः मिहलाओं को राजनीति से दूर रखने में पुरुषों और मिहलाओं के बीच घरेलू काम का असमान वतरण भी महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है। पुरुषों की तुलना में मिहलाओं को पिरवार में अधक समय देना पड़ता है और घर तथा बच्चों की देखभाल का जि़म्मा प्रायः मिहलाओं को ही संभालना पड़ता है। बच्चों की आयु बढ़ने के साथ मिहलाओं की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं।

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- राजनीति में रु च का अभावः राजनीतिक नीति-निर्धारण में रु च न होना भी महिलाओं को राजनीति में आने से रोकता है। इसमें राजनीतिक दलों की अंदरूनी गित व धयाँ और इज़ाफा करती हैं। राजनीतिक दलों के आतंरिक ढाँचे में कम अनुपात के कारण भी महिलाओं को अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख के लये संसाधन और समर्थन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा, मिहलाओं पर थोपे गए सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व भी उन्हें राजनीति में
 आने से रोकते हैं।

आगे की राह

- भारत जैसे देश में मुख्यधारा की राजनीतिक गित व धयों में मिहलाओं को भागीदारी के समान अवसर मलने चाहिये।
- महिलाओं को उन अवांछित बाध्यताओं से बाहर आने की पहल स्वयं करनी होगी जिनमें समाज ने जकड़ा हुआ है, जैसे क महिलाओं को घर के भीतर रहकर काम करना चाहिये।
- राज्य, परिवारों तथा समुदायों के लये यह बेहद महत्त्वपूर्ण है क शक्षा में लैं गक अंतर को कम करना, लैं गक आधार पर कये जाने वाले कार्यों का पुनर्निधारण करना तथा श्रम में लैं गक भेदभाव को समाप्त करने जैसी महिलाओं की व शष्ट आवश्यकताओं का समु चत समाधान निकाला जाए।
- राज्य वधानसभाओं और संसदीय चुनावों में मिहलाओं के लये न्यूनतम सहमत प्रतिशत
 सुनिश्चित करने हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लये इसे अनिवार्य बनाने वाले भारत
 निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव (इसे गल फॉर्मूला कहा जाता है) को लागू करने की आवश्यकता है।
 जो दल ऐसा करने में असमर्थ रहेगा उसकी मान्यता समाप्त की जा सकेगी।
- वधायिका में महिलाओं के प्रतिनि धत्व का आधार न केवल आरक्षण होना चाहिये, बल्कि इसके
 पीछे पहुँच और अवसर तथा संसाधनों का सामान वतरण उपलब्ध कराने के लये लैं गक
 समानता का माहौल भी होना चाहिये।

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

निर्वाचन आयोग की अगुवाई में राजनीतिक दलों में मिहला आरक्षण को प्रोत्साहित करने के
 लये प्रयास कये जाने चाहिये। हालाँ क इससे वधायिका में मिहलाओं की संख्या तो सुनिश्चित
 नहीं हो पाएगी, ले कन जिटल असमानता को दूर करने में इससे मदद मल सकती है।

जनता से चुने गए प्रतिनि धयों से मलकर लोकसभा बनी होती है जिन्हें वयस्क मता धकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। सं वधान में उल्लि खत सदन की अधकतम क्षमता 552 सदस्यों की है जिनमें 530 सदस्य राज्यों का व 20 सदस्य केंद्रशा सत प्रदेशों का प्रतिनि धत्व करते हैं और 2 सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदायों के प्रतिनि धत्व के लए राष्ट्रपति द्वारा नामां कत कया जाता है। ऐसा तब कया जाता है , जब राष्ट्रपति को लगता है क उस समुदाय का सदन में पर्याप्त रूप से प्रतिनि धत्व नहीं हो रहा है। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। यहां लोकसभा कार्यकाल का एक सं क्षप्त इतिहास दिया गया है...

महिलाओं को राजनीति में कमज़ोर बताए जाने को लेकर दिए जाने वाले तर्क-महिला कैं डडेट के जीतने की उम्मीद बहुत कम होती है।

महिलाएं अपने घरेलू काम के बीच राजनीति में एक पुरुष के मुकाबले समय नहीं दे पाती हैं। महिलाओं को राजनीतिक समझ कम होती है इस लए अगर वे जीतकर भी आती हैं तो महिला वभाग, शशु वभाग जैसे क्षेत्र तक सी मत रखा जाता है। हालां क आज इसके अपवाद भी देखने को मल रहे हैं, जिसका एक बेहतर उदाहरण डफेंस मनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं।

- 1. जहां तक बात है महिला कैं डडेट के जीतने की तो अंतिम तीन लोकसभा चुनाव में महिला कैं डटडेट के जीतने का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा रहा है। 2014 के चुनाव में महिला कैं डडेट का सक्सेस रेट 9 प्रतिशत था जब क पुरुषों का 6 प्रतिशत।
- 16वें लोकसभा चुनाव में जीतकर आई महिला कैं डडेट की संख्या सबसे ज़्यादा थी। बावजूद आज भी कई राजनीति पार्टियां महिलाओं को तवज्जों नहीं देती हैं, इसका असर होता है क बहुत कम ही महिलाएं एक्टिव पॉ लटिक्स में आ पाती हैं।

राजनीति में नेपोटिज़्म और महिलाएं

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

खासकर सक्योरिटी के मामले में।

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कई महिलाएं चुनाव जीतकर तो आती हैं ले कन उन्हें कहां, क्या और कैसे फैसले लेने हैं, इस सबका निर्धारण उनके घर के पुरुष ही करते हैं। हालां क यह स्थिति पंचायत चुनावों में ज़्यादा देखने को मलती है। वधानसभा और लोकसभा चुनाव के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है।

राजनीति में नेपोटिज़म पर बात करते हुए इजया यादव कहती हैं क मुखया के स्तर पर घर के पुरुष हावी ज़रूर होते हैं, जिसका बड़ा कारण ग्रामीण परिवेश और उस महिला की शक्षा में कमी होती है ले कन वधानसभा के स्तर पर ऐसा नहीं है। अगर एक पुरुष भी MLA है तो परिवार के सहयोग के बिना वह काम नहीं कर पाएगा। राजनीति एक इंसान की बस की बात नहीं है, परिवार का इंगेजमेंट होता ही है। वह आगे बताती हैं, 'मैं ही MLA हूं, मैं सबकुछ खुद कर तो लेती हूं ले कन मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है ,

वहीं अमृता बताती हैं क मुखया लेवल पर नेपोटिज़्म की समस्या है , क्यों क ग्रामीण इलाकों में महिलाएं ज़्यादा निकलती नहीं हैं ले कन आपको एक निश्चित प्रतिशत में महिला कैं डडेट को लाना ही होता है। इस तरह वे पुरुष जो अपना अस्तिव बनाए रखना चाहते हैं , वे अपनी पत्नियों को खड़ा करना चाहते हैं। इस परिस्थिति में उनको मजबूरी भी है महिला को खड़ा करना।

वधानसभा, लोकसभा स्तर पर नेपोटिज़्म पर बात करते हुए अमृता कहती हैं, 'इस स्तर पर नेपोटिज़्म की स्थिति कम होती है ले कन ऐसा नहीं है क बिलकुल ही नहीं है। कोई कद्दावर नेता जो कसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो अपनी पत्नी को खड़ा करता है। हालां क यह स्थिति बेहद कम देखने को मलती है।"

इस प्रकार कहा जा सकता है क वर्तमान समय में राजनीति में महिलओं का योगदान बढता जा रहा है। 2019 के आम चुनाव में उनकी स्थिति काफी अच्छी हुई है। आज के समय में महिलए भी राजनीति में बढ चढ कर हिस्सा लें रही है।

संदर्भ

Vol.9 Issue 11, November 2019,

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com

Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- 1. संजय गौड, "आधुनिक महिलायें और सामज उत्पीड़न अत्याचार एवं अ धकार"
- 2. महात्मा गाँधी : यंग इं डया
- 3. भारत का संवधान
- 4. रू च श्री वास्तव, "महिला संशक्तिकरण के लए समाज के प्रत्येक वर्ग का मान सक संशक्तिकरण"
- 5. संजय गौड, 'महिलाओं का राजनैतिक परिदृश्य
- 6. क्रौनिकल बुक्स समूहः भारत की सामाजिक समस्याएँ,
- 7. https://loksabha.nic.in/Members/